

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 482/2024

सतवीर

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार,  
सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वाहन चालक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर से कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। उसका स्थानान्तरण 400 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने की दृष्टि से एवं निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी के द्वारा सीकर में अपना स्थानान्तरण चाहा गया है एवं उसकी प्रार्थना पर उनका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता हृदय रोग से पीड़ित है, ऐसे में अपीलार्थी को स्थानान्तरण से विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसकी प्रार्थना पर किया जाना तब तक गलत नहीं माना जा सकता जब तक उसमें कोई दुर्भावना नहीं रही हो। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी के समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात उसका स्थानान्तरण किया गया है। हमारे सामने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही है।
5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

*"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government*

*and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक कठिनाइयों को दर्शाते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

7. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन होने से कारण इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)